unit-1 (c)

B.A. II - Sem. IV

Paper - C8.

History of West Asia

दो विश्वयुद्धों के बीच फिलिस्तीन की समस्या

फिलिस्तीन यहूदियों का निवास है। सभ्यता के प्रारंभ से वे यहीं रहते थे और यहीं से संसार के कोने-कोने में फैले थे। सातवीं शताब्दी में इस भूभाग पर अरबों का आधिपत्य हो गया। अरबों के बाद फिलिस्तीन पर तुर्कों का अधिकार हो गया और वह ओटोमन साम्राज्य का एक अंग बनकर रहा।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ और फिलिस्तीन पर राष्ट्रसंघ के निर्णय के अनुसार ब्रिटेन का संरक्षण शासन कायम हुआ। 1920 से 1948 ई० तक इस राज्य पर इंगलैंड का संरक्षण शासन रहा। इस काल में फिलिस्तीन के अरबों और यहूदियों में भीषण संघर्ष हुए। यहूदी फिलिस्तीन को अपना 'राष्ट्रीय आवास' बनाना चाहते थे और अरब वहाँ यहूदियों को रहने देना नहीं चाहते थे। इसको लेकर दोनों जातियों में भीषण संघर्ष हुआ।

फिलिस्तीन समस्या के संदर्भ में अरबों और यहूदियों ने अपने-अपने दावे पेश किए -

अरबों का कहना था कि 7वीं शताब्दी से ही वे वहाँ रहते आ रहे हैं। फिलिस्तीन के सभी आर्थिक साधनों पर उनका अधिकार है। फिलिस्तीन की समग्र संस्कृति अरब सभ्यता संस्कृति हो गई है। यह अरबों का राष्ट्रीय दावा था।

इसके अतिरिक्त उनके राजनीतिक दावे

Scanned with CamScanner

दावे भी थी। प्रथम विश्वयुद्ध के समय अरबों को यह आश्वासन दिया गया था कि तुर्की की पराजय के बाद अरबों के स्वतंत्र राज्य कायम होंगे अतः इस आश्वासन के आधार पर वहाँ उनका ही राज्य होना चाहिए। इस तरह फिलिस्तीन पर उनका राजनीतिक दावा भी था।

दूसरी ओर यहूदी फिलिस्तीन को अपना मूल निवास मानते थे। उनका कहना था कि आक्रमणकारियों ने उनपर हमला कर मातृभूमि छोड़ने को बाध्य किया। विदेशों में भी उनपर घोर अत्याचार हो रहे हैं। अतः वे स्वदेश लौटना चाहते हैं। अरबवालों यहाँ के आर्थिक साधनों पर अन्यायपूर्ण अधिकार कर लिया है।

अब यहूदी राजनीतिक रूप से संगठित होने लगे। क्योंकि उनके प्रारंभिक नेता थियोडोर हर्जल ने कहा कि यहूदी प्रश्न एक राष्ट्रीय समस्या है, जिसे केवल राजनीतिक समस्या बनाकर ही हल किया जा सकता है। उन्होंने जियोनी आंदोलन की नींव डाली। 1897 ई० में स्विट्जरलैंड में यहूदियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में राष्ट्रीय आवास की मांग की गई।

आरंभ में ब्रिटिश सरकार उन्हें सिनाई प्रायद्वीप का एक भाग देने को राजी हुई, लेकिन यहूदियों ने इसे इंकार कर दिया। फिर अफ्रीका में युगांडा का एक भूभाग देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन यहूदियों को यह मान्य नहीं हुआ। 1904 ई० में यहूदियों के नेता हर्जल की मृत्यु हो गई। लेकिन यहूदी इससे आहत नहीं हुए बल्कि संसार भर में फैले हुए यहूदी अत्यंत संगठित रूप में फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। इसी समय यहूदियों के कई संगठन बने। यहूदी राष्ट्रीय कोष और फिलिस्तीन स्थापना कोष महत्वपूर्ण यहूदी संगठन थे। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन को यहूदी राज्य बनाना था।

प्रथम विश्वयुद्ध के काल में जियोनी आंदोलन में काफी प्रगति हुई। यहूदियों के नेता

वाइजमैन ने अंग्रेजों की सहानुभूति पाने के लिए ब्रिटिश फिलिस्तीन समिति का निर्माण किया। इस समिति का उद्देश्य था - फिलिस्तीन में पुनः यहूदी राज्य की स्थापना करना।

बालफोर घोषणा - यहूदी आंदोलन के प्रति इंगलैंड में सहानुभूति बढ़ने लगी। अतः 2 नवम्बर 1917 को लार्ड बालफोर ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि "ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदी जाति के लिए एक राष्ट्रीय आवास के पक्ष में है और इसे सरलतापूर्वक करवाने के लिए प्रयासरत रहेगी।

बालफोर घोषणा से यहूदियों को कानूनी आधार मिल गया।

फिलिस्तीन पर ब्रिटिश संरक्षण -

1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में फिलिस्तीन पर ब्रिटिश संरक्षण का निर्णय लिया गया। इससे ब्रिटेन लाभान्वित हुआ। सन् 1922 में सर सैमुएल को फिलिस्तीन का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसी बीच अरबों और यहूदियों के बीच वेलिंगवाल का झगड़ा हो गया।

वेलिंगवाल का झगड़ा -

जेरूसलम में स्थित वेलिंगवाल एक पवित्र स्थान है, जिसे अरब और यहूदी दोनों पवित्र मानते हैं। इस स्थान पर दोनों को अलग करने के लिए एक पृथक दीवार थी जिसके निकट खड़ा होकर यहूदियों को प्रार्थना करने की इजाजत थी लेकिन यहूदियों ने 24 सितम्बर 1928 को दीवार के पास एक पक्की दीवार खड़ी कर दी। इस पर अरब पुलिस आकर दीवार को हटा दी। अतः दोनों के बीच सांप्रदायिक दंगे हो गए।

इस विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिम्पसन आयोग गठित किया। आयोग ने सिफारिश

थी कि यहूदियों के आगमन को पूरी तरह बंद कर दी जाए। इसके खिलाफ यहूदियों ने विश्वव्यापी आन्दोलन आरंभ कर दी अतः 1932 ई० में अंग्रेज सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन लाना पड़ा। लेकिन अरब और यहूदी अपने संघर्ष जारी रखे। ब्रिटिश सरकार ने उपद्रवों की जाँच के लिए एक आयोग गठित की। इसके अध्यक्ष लार्ड पील थे।

पील आयोग -

पील आयोग ने सुझाव दिया कि संरक्षण शासन को समाप्त कर दिया जाए और फिलिस्तीन को 3 भागों में बाँट दिया जाए। एक भाग यहूदियों को, एक भाग अरबों को, एक निरपेक्ष क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत रहेगा जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमील हो।

लेकिन इसकी सर्वत्र आलोचना हुई। अतः सर जॉन उडहेड की अध्यक्षता में 1938 ई० में कमिटि गठित की गई। इसने फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया। अतः अंग्रेज सरकार ने अरबों और यहूदियों के बीच समझौते के लिए 1939 ई० में गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया। लेकिन दोनों अपनी मांग पर अड़े हुए थे।

अतः ब्रिटिश सरकार ने 17 may 1939 ई० को एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इसमें कहा गया कि 10 वर्षों में फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा। अरबों और यहूदियों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसी बीच 1939 ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। 1945 ई० में विश्वयुद्ध समाप्त हुई। वहाँ मजदूर दल की सरकार बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि यहूदियों को फिलिस्तीन में आकर बसने की आज्ञा दे। अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त समिति ने फिलिस्तीन को एक संघराज्य का रूप देने का सुझाव दिया। अंततः 1948 ई० में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपने संरक्षण समाप्त कर दिया। इसी दिन फिलिस्तीनियों ने तेलअवीव में इजरायल नामक राज्य की घोषणा कर दी।

000

R.K. DSPMU.